स्मार्ट सिटी में जिन्दगी बनकर दौड़ेंगी कैट्स एंबुलेंस

स्मार्ट सिटी

मुरादाबाद | वरिष्ठ संवाददाता

शहर को स्मार्ट बनाने की मुहिम में स्वास्थ्य विभाग भी अपना योगदान देने की कवायद में जुट गया है। स्मार्ट सिटी मुरादाबाद में कैट्स एंबुलेंस दौड़ेंगी। ये एंबुलेंस हाइवे पर हादसे में घायल लोगों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाएंगी। एंबुलेंस हाइवे पर रेस्क्यू प्वाइंट बनाकर खड़ी की जाएंगी।

मुरादाबाद को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में स्मार्ट बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्मार्ट सिटी की मुहिम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव तैयार करके भेजा है। जिसमें दिल्ली समेत कुछ मेट्रो शहरों की तर्ज पर कैट्स (सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्विस) के अधीन एंबुलेंस चलाने की व्यवस्था होगी। यह एंबुलेंस नेशनल एंबुलेंस सर्विस (एनएएस) के तहत संचालित 102 और 108 एंबुलेंस से अलग होंगी। इन एंबुलेंसों को संबंधित ट्रॉमा सेंटर के साथ ही हाइवे पर रेस्क्यू प्वाइंट बनाकर खड़ा किया जाएगा। निर्धारित नंबर पर कॉल करते ही एंबुलेंस दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाएगी।

नगर निगम को देनी होगी सफाई की रिपोर्ट: गन्दगी के कारण तमाम बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों को रोकने में नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है। स्मार्ट सिटी में जल और मच्छर जनित बीमारियों से बचाव को लेकर नगर निगम को जवाबदेह बनाया जाएगा। नाले साफ करने, सिल्ट उठाने, जलभराव नहीं होने देने, फॉगिंग करने आदि सुनिश्चित करके नगर निगम को स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट देनी होगी।

बचाएंगी जान

- सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्विस के तहत हादसे में घायलों को पहुंचाएगी ट्रॉमा सेंटर
- ट्रॉमा सेंटर के साथ ही हाइवे पर रेसक्यू प्वाइंट बनाकर खड़ी की जाएंगी ये एंबुलेंस
- स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार को भेजा कैट्स एंबुलेंस के संचालन का प्रस्ताव

स्वास्थ्य विभाग मुरादाबाद को स्मार्ट शहर बनाने की प्रक्रिया में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने की तैयारी में जुट गया है। जिले में नई सेवाएं और सुविधाएं शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
– डॉ .रंजन गौतम, नोडल अधिकारी

सरकारी ट्रॉमा सेंटर के लिए दूसरी किस्त जारी

मुरादाबाद। जिला अस्पताल परिसर में सरकारी ट्रॉमा सेंटर के निर्माण की रफ्तार अब और तेज हो जाएगी। इसके लिए दूसरी किस्त शासन द्वारा जारी कर दी गई है। निर्माण के लिए कुल एक करोड़ 86 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। शासन की तरफ से निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश जारी हुआ है।मुरादाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर लंबे समय के इंतजार के बाद स्वीकृत हुआ और फिर बड़ी मुश्किल से निर्माण कार्य शुरू हो सका। शासन द्वारा निर्माण कार्य के लिए पहली किस्त के रूप में 39 लाख रुपए मंजूर किए गए। काफी जद्दोजहद के बाद जिला अस्पताल में ओपीडी के सामने ट्रॉमा सेंटर बनना शुरू हुआ। ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग का निर्माण कार्य नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। नोडल अधिकारी डॉ.रंजन गौतम ने बताया कि निर्माण के लिए दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। इसके बाद निर्माण कार्य में और तेजी लाने को कहा गया है। शासन ने इसे जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया है।

शहर में खुलेगा सरकारी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल

स्मार्ट सिटी मुरादाबाद में सरकारी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल खोलना भी प्रस्तावित है। डॉ.रंजन गौतम ने बताया कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हार्ट सर्जरी, घुटना, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्पेशलाइज्ड बर्न वार्ड आदि की सुविधा उपलब्ध होगी।

स्मार्ट सिटी में डिलीवरी हट बनेंगे शहरी स्वास्थ्य केंद्र

अर्बन हेल्थ पोस्ट को अर्बन एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल और डिलीवरी हट के रूप में विकसित किया जाएगा। इन शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को जाने वाली सड़कों को दुरुस्त करने, 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति, हाईमास्ट लाइट आदि की व्यवस्था होगी।

संक्षेप

वैट के नोटिस से अधिवक्ता नाराज

मुरादाबाद। वैट अधिनियम की धारा 45(1)की नोटिस से अधिवक्ता नाराज हैं। बुधवार को जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और नोटिस का विरोध किया। संगठन के गुफरान माजिद, अनुज गुप्ता, सचिन अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, राकेश कुमार शर्मा, संजीव माहेश्वरी, दीपक कुमार गुप्ता, सईद आरिफ अली आदि ने आग्रह किया कि इस धारा के आधार पर सभी फर्मों को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। ज्ञापन देकर कहा गया कि मंडल के कई खंडों में अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को नोटिस जारी करना सही नहीं है। इसे रोका जाए। नोटिस में फार्म 24 का उपयोग हो।

बुधवार को वाणिज्यकर एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन देते जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य।

गोविंदनगर में नगर आयुक्त को मिली गंदगी

मुरादाबाद। नगर आयुक्त व अफसरों ने कई क्षेत्रों में गंदगी के ढेर मिले। गोविंदनगर में साफ न होने पर जहां नाराजगी जताई। खफा नगर आयुक्त ने सफाई निरीक्षक अमित कुमार को आड़े हाथ लिया और अभियान चलाकर कराई कराने को कहा। पार्षद गगन शर्मा ने सफाई व्यवस्था ठप होने पर शिकायत की थी। नगर आयुक्त को वार्ड-33 में भी गंदगी मिली। जबकि हरथला में नाली का पानी सड़क पर जा रहा था। सफाई निरीक्षक अजयशील को सफाई कराने के निर्देश दिए गए।

गन्ना उपायुक्त से मिला भाकियू प्रतिनिधिमंडल

बिलारी। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन असली व अराजनैतिक का धरना-प्रदर्शन 87वें दिन भी जारी रहा।भाकियू का प्रतिनिधिमंडल मुरादाबाद में उप गन्ना आयुक्त से मिलकर वार्ता की। गन्ना आयुक्त राजेश मिश्रा ने किसानों को आश्वासन दिया कि हर हाल में नौ नवंबर तक उनका समस्त भुगतान मिल जाएगा। वहीं कहा कि मिलें समय पर चलेंगी। किसानों ने कहा कि गन्ना भुगतान न मिलने से किसानों की कमर टूट चुकी है। किसानों का शोषण किया जा रहा है।

समस्याओं पर रोडवेजकर्मी शुक्रवार को देंगे धरना

मुरादाबाद। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले रोडवेजकर्मी शुक्रवार को पीतलनगरी डिपो के कार्यशाला गेट पर धरना देंगे। संगठन के शाखा मंत्री अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि विभाग संगठन के कई समझौतों पर अमल नहीं कर रहा है। एक से सात नवंबर तक कर्मचारी गेट पर सभा करेंगे और चार से पांच नवंबर तक रात के बारह बजे से दिन के बारह बजे तक चक्का काम किया जाएगा। वहीं संगठन ने 29 अक्टूबर को आन्दोलन का ऐलान स्थगित कर लिया गया है। बुधवार को अधिकारियों से वार्ता के बाद संगठन ने यह निर्णय लिया है। ट्रैफिक शाखा के मंत्री उमेश चंद्र ने यह जानकारी दी है। कहा है कि वार्ता काफी सुखद रही है।

हाउस और वाटर टैक्स के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर

ऑनलाइन टैक्स भरेंगे 13 मोहल्लों के बाशिंदे

सहूलियत

मुरादाबाद | राजेश भाटिया

शहरी उपभोक्ताओं को टैक्स जमा के लिए नगर निगम दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हाउस व वाटर टैक्स कितना और कब तक बकाया है। यह सब वे आसानी से घर बैठे जान सकेंगे। नगर निगम में टैक्स जमा करने की ऑनलाइन सुविधा से तेरह मोहल्ले जुड़ रहे है। निगम में उपभोक्ताओं के नाम, आईडी नंबर कंप्यूटर में फीड कर दिए हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

उपभोक्ताओं को टैक्स जमा करने के लिए पहले अक्सर परेशानियों से जूझना पड़ता था। लोगों को टैक्स की रसीद नहीं मिल पाती थी। इसमें राहत के लिए प्रणाली को हाइटेक करने की निगम ने सोची। दो साल की लंबी कवाय के बाद ऑनलाइन टैक्स प्रणाली से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। टैक्स प्रणाली को ऑनलाइन का काम पूरा हो गया है। शुरुआत तेरह मोहल्ले से होगी। पीरगैब, फैजगंज समेत 13 मोहल्लों के उपभोक्ता अपना टैक्स ऑनलाइन के जरिए जमा कर सकेंगे। निगम की माने तो इन शहर के इन क्षेत्रों के नाम और आईडी को कंप्यूटर में फीड करने का काम पूरा हो गया है। जानकार कहते है कि अभी वेबसाइट पर उपभोक्ता अपने टैक्स का पता लगा सकता है।

शासनादेश के बाद भी लगा दी टैक्स अफसरों की चुनाव में ड्यूटी: जिले में हुए पंचायत चुनावों से सियासी गुणाभाग भले ही हुआ हो मगर चुनाव से नगर निगम का कामकाज प्रभावित हुए बगैर नही रह सका। चार चरणों के चुनाव से निगम की कार्यप्रणाली पर बुरा असर पड़ा। निगम के ज्यादातरों की डयूटी से विभाग के कामकाज का ढर्रा बदल गया। चुनाव में सफाई निरीक्षक, निर्माण से लेकर कर अफसरों को डयूटी में झोंका गया। चुनाव में दो मुख्य सफाई निरीक्षकों की डयूटी लगी। निरीक्षक के जिम्मे शहर में सफाई के कई इलाके है। इससे दर्जनों मुहल्लों का सफाई व्यवस्था चरमरा गई। निगम में गिने चुने टैक्स अफसर भी नहीं बख्शे गए। इसका असर वसूली पर पड़ा है। राजस्व वसूली 50 फीसदी भी नहीं हो सकी। जबकि वसूली दो करोड़ प्रतिमाह वसूली रहने का औसत है। चुनावी डयूटी से निगम का निर्माण विभाग भी बच न सका। एई, जेई तक की डयूटी लगी। लिहाजा निगम का कामकाज ठप है।

स्मार्ट सिटी में बदलाव

- मंडी चौक, गलशहीद इलाकों में पहले शुरू हुई व्यवस्था
- गृह-जलकर जमा करने को लाइन में नहीं लगना होगा
- ऑनलाइन टैक्स की कवायद अंतिम चरण में, डाटा फीड हुए

इन मोहल्लों के लिए सुविधा

शहर के जिन इलाकों में यह सुविधा प्राथमिक तौर पर शुरू की जा रही है उनमें पीरगैब, फैजगंज, बाजी गरान, पान दरीबा, मो. अताई, काला प्यादा, पक्की सराय, खोखरान, पुजारी गली, गलशहीद का आंशिक मोहल्ला शामिल हैं। और मोहल्लों में भी यह सुविधा शुरू होगी।

टैक्स जमा करने के लिए ऑन लाइन प्रक्रिया की तैयारी पूरी हो गई है। ऑन लाइन सिस्टम को तेजी से करने को अफसरों की टीम भी बनाई गई है। ताकि लोगों को सुविधा का जल्दी लाभ मिल सकें।
–संजय कुमार सिंह, नगर आयुक्त

बुधवार को कश्मीर हाउस में वाणिज्यकर विभाग के शिविर में पंजीकरण के बाद व्यापारियों को कागजात सौंपते अफसर।

शिविर में व्यापारियों ने कराए पंजीकरण

मुरादाबाद | कार्यालय संवाददाता

सेल्सटैक्स विभाग में बुधवार को लगाए गए शिविर में कई व्यापारियों ने अपनी फर्मों का पंजीकरण कराया। इस मौके पर विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों और अधिवक्ताओं को विभाग से जारी होने वाले टिन से व्यापार के लाभ बताए।

बर्तन बाजार में डिप्टी कमिश्नर वीके झा और असिस्टेंट कमिश्नर अरविन्द कुमार सिंह की देखरेख में पांच पंजीयन पत्र दाखिल किए गए। जांच के बाद ऑनलाइन दो फर्मों को टिन जारी कर दिया गया। जरूरी कागजात नहीं होने की वजह से तीन फर्मों की औपचारिकता पूरी नहीं हो पाई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजीकृत कारोबारी किसी भी सरकारी जांच से प्रभावित नहीं होगा और सरकार की ओर से मिलने वाली सहूलित उसे मिलती रहेगी। अधिवक्ता राकेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, अंमबरीश अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, गौरव शर्मा, व्यापारी प्रतिनिधि अजय अग्रवाल शिविर में प्रमुख रूप से शामिल रहे। उधर, चौमुखा पुल चौराहा के पास लगे शिविर में व्यापारी कल्याण समिति के सदस्यों ने इस पहल का स्वागत किया। संगठन के प्रदेश महामंत्री सुनील कत्याल, नीरज मित्तल आदि ने अभियान में मदद की। कश्मीर हाउस के शिविर में तीन पंजीकरण हुए, यहां पर विभाग के एसी बृजेश कुमार और डीसी शशि आर्य मौजूद रहीं।

पन्द्रह दिन रहेगी त्योहारों की धूम

मुरादाबाद। अक्टूबर माह के अन्तिम सप्ताह से आने वाले 15 दिन तक धार्मिक पर्वों की बयार बहेगी। इस बीच महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी तो अहोई आदि के व्रत से बच्चों के लिए भी सुख-शांति की पूजा करेगी। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन व भईयादूज पर महिलाएं अपने भाईयों के घर जाकर टीका करेंगी। इस तरह पूरे पंद्रह दिन घर में पूजा पाठ के साथ पकवान बनाने का क्रम चलेगा।

ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया सीखी

मुरादाबाद | कार्यालय संवाददाता

विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया में धांधली रोकने के मकसद से नगर निगम ने बुधवार को सभी ठेकेदारों को ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के बारे में समझाया। ठेकेदार कैसे देखें और कैसे आवेदन करें, इसकी जानकारी दी गई। नगर निगम से 20 करोड़ के विकास कार्यों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

13वें व 14 वें वित्त के निर्माण व जलकल से संबंधित बीस करोड़ के कामों को मंजूरी मिली है। निगम ने कामों की टेंडर वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। निगम ने पहली बार ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे तमाम ठेकेदार चकरा गए। टेंडर डालने को लेकर ठेकेदार दुविधा में है। समस्या के हल के लिए निगम ने बुधवार को बाकायदा ई. टेंडरिंग प्रक्रिया के बारे में ठेकेदारों को प्रोजेक्टर के जरिए बताया। ठेके किस तरह से देखे और आवेदन करें, इस पर निगम के आईटी व अन्य जानकारों को बुनियादी बातें समझाई। बैठक में नगर आयुक्त संजय कुमार सिंह, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी टीएन मिश्र, एई रमाकांत के अलावा बड़ी संख्या में ठेकेदार मौजूद रहे।

PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LIMITED
(Formerly known as Prakash Woollen Mills Limited)
CIN L17291UP1979PLC004804
Regd. Office: 18th Km Stone, Delhi Moradabad Road, NH-24, Village Amhera, Distt J P Nagar, Uttar Pradesh-244102

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to clause 41 of the Listing Agreement with the Stock Exchange, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 7th November, 2015 at its Registered office to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results, for the quarter ended 30th September, 2015 among other things.

For PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LIMITED
Shivangi Agarwal
Company Secretary

Place : Vill-Amhera (Amroha)
Date : 28.10.2015

ठेके के पास खाली जगह पर लगेंगी पटाखे की दुकानें

मुरादाबाद। मोक्षधाम पर दो सालों से लग रही पटाखे की दुकानें इस बार शराब ठेके के पास खाली पड़ी जगह पर लगेंगी। स्थान बदलने की वजह लोकोशेड पुल के काम में लगे सेतु निगम के गोदाम और साइड आफिस का खुलना है। धनतेरस से बड़ी दीवाली तक तीन दिन को मोक्षधाम पर लगने वाली पटाखे की दुकानों के स्थान में बदलाव किया गया है। दुकानें की बुकिंग के काम में लगे दिनेश कुमार का कहना है कि इस बार भी चालीस से पैंतालिस दुकानें लगनी हैं, इसके लिए बुकिंग चल रही है। इन दुकानों के साथ ही कंपनी बाग में लगने वाली दुकानें अब पारकर इंटर कालेज के मैदान में लगेंगी।

बंद हो गया परिवार नियोजन कार्यक्रम!

मुरादाबाद। एक तरफ प्रदेश में आबादी की बढ़ती रफ्तार थामने की जद्दोजहद तेज हो गई है। वहीं मुरादाबाद में आपरेशन करने में कोई प्रशिक्षित महिला चिकित्सक नहीं होने से नसबंदी ऑपरेशन बंद हो गए हैं। मुरादाबाद समेत यूपी में जनसंख्या वृद्धि की दर (टीएफआर) काफी ज्यादा है। इसे घटाने के लिए मिशन 2020 शुरू हुआ है। सीएमओ डॉ.संजीव यादव का कहना है कि परिवार नियोजन के ऑपरेशन करने में प्रशिक्षित एक महिला रोग विशेषज्ञ का रिटायर हो जाना और दूसरी विशेषज्ञ का तबादला होने की वजह से अब जिले में कोई प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं रह गई है।

Sunflame®
THE CLEAR CHOICE

Celebrate Festive Season
with fabulous offers from Sunflame

SUPER DUPER OFFER

Exchange your old gas cooktop any make, any condition for a sparkling new Sunflame Cooktop and
SAVE UPTO ₹ 2,500/-*
PLUS ALSO GET
MG STYLE 3 JAR + IRON OPAL
WORTH ₹ 4,190/-
ABSOLUTELY FREE

EK KA TEEN OFFER
Buy Star JMG

MRP. ₹ 3,795/-
AND ALSO GET
Solitaire Induction Base Pressure Cooker (3 Ltr.) + Popular Iron
WORTH ₹ 2,005/-
ABSOLUTELY FREE*

VENZA 60 SS/BK BF + CLASSIC 4B BK

Suction 1100 m³/hr WITH BAFFLE FILTER
Combined MRP. ₹ 27,280/-

Offer Price ₹ 14,990/-**

*Offer on MRP. (MRP. mentioned are inclusive of all taxes) **Handling Charges ₹ 300/- extra
Hurry! Offers available for limited period
foundations
Visit us at www.sunflame.com
Available at all leading stores.
FOR TRADE ENQUIRY- MORADABAD- 9719166077, 9627795000, 9457502457 MORADABAD -AUTHORISED SERVICE CENTRE - 0591-2323857,
FOR TRADE ENQUIRY- RAMPUR- 9719166077, 9627795000, 9457502457,RAMPUR AUTHORISED SERVICE CENTRE -9639576415

हिन्दुस्तान
हिन्दुस्तान महा उत्सव 2015
निश्चित उपहार योजना#
क्या आप पांचवीं पास से तेज हैं?
अगर हां तो दीजिए आसान सवालों के जवाब और बनाइए इस उत्सव के मौसम को महा उत्सव

#विजेताओं का निर्धारण लकी ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। ## नियम व शर्तें लागू।
एक ऐसा खेल जिसमें आप ईनाम के साथ अपना ज्ञान भी बढ़ाएंगे.
तो काटो सही जवाब ....
प्रश्नों के लिए आज ही अपने वितरक से बुक कराएं हिन्दुस्तान
Source IRS 2014, Delhi, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand
योजना कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए
हिन्दुस्तान की प्रति सुनश्चित कराने हेतु सम्पर्क करें- मुरादाबाद शहर : 7055136777, 7088962325, 9690200444 मुरादाबाद देहात : 8954477803 रामपुर : 8941002041 सम्भल : 7060402059 चन्दौसी : 8938805526 अमरोहा : 9997601333, 9897978007
हिन्दुस्तान तरक्की को चाहिए नया नजरिया
हिन्दी क्षेत्र का नं.1 अखबार

I have made it very clear that it is a valid regulation. It has been neither overturned by a competent authority, nor has been it annulled, modified or cancelled. The operators must take steps to prepare themselves to implement this

TRAI CHAIRMAN RS SHARMA

BUZZ FROM TRAI & CORP

After overcoming significant challenges and under the new ownership, SpiceJet has not only returned to profitability, it has been a fundamental catalyst behind the world leading market growth in India. Thanks to SpiceJet, competition has been kept alive in the Indian airline industry

SPICEJET CHIEF OPERATING OFFICER SANJIV KAPOOR

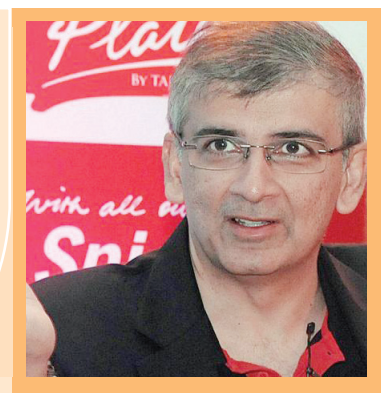

Call drops: Telcos express concern on compensation, but TRAI says rules to stay

TRAI and mobile operators have decided to meet every fortnight to sort out issues related to call drops

PNS ■ NEW DELHI

Mobile operators on Thursday expressed their concerns about compensation norms before the Government and pitched for possible solution for the problem, but telecom regulator Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) conveyed them about consumers' concern instead, saying that regulation on call drops is valid and asked the operators to compensate consumers for every dropped call from January 1.

In a meeting held in the national capital, both TRAI and mobile operators decided to meet every two weeks, to sort out issues and concerns surrounding call drops. On the other hand, the regulator asked mobile service providers to ready their systems to compensate consumers for the call drops from January 1 and in the meantime, it expressed its willingness to examine the issues raised by them as well.

"I have made it very clear that it is a valid regulation. It has been neither overturned by a competent authority, nor has been it annulled, modified or cancelled. The operators must take steps to prepare themselves to implement this," Trai Chairman RS Sharma told reporters on Thursday.

However, a TRAI official said, "The two sides had decided that the joint team of officials from TRAI and mobile phone companies would assess the test results on networks, planned in Delhi, Mumbai, and five other cities by December."

The meeting was attended by Bharti Airtel India Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) Gopal Vittal, Vodafone India MD and CEO Sunil Sood, Idea Cellular MD and CEO Himanshu Kapania, Reliance Jio Infocomm MD Sanjay Mashruwala and MTNL Director Sunil Kumar.

Industry body Cellular Operators Association of India (COAI), DG Rajan S Mathews, Association of Unified Telecom Service Providers of India (AUSPI) Secretary General Ashok Sud and representatives of other telecom companies were also present. Telecom operators have also questioned selection of the areas by the regulator for testing call drops.

The regulator had already held a meeting with telecom operators on implementation of call drop compensation rules and steps taken by them to improve quality of service. According to the guidelines, telecom operators will have to compensate consumers ₹1 for every call drop that occurs due to fault in their network, which is limited to a maximum of ₹3 a day per consumer.

Telecom operators have questioned the regulator's jurisdiction to impose such rules on them and technical feasibility of its implementation. "An impression is being created that the authority has imposed this regulation without considering the technical feasibility of its operation. Before issuing regulation, the authority has considered all aspects of the matter, including technical feasibility," Sharma said.

Industry bodies such as COAI and AUSPI have written a letter to the regulator that implementation of the rules may lead to higher mobile call rates. "The industry bodies want us to review the decision. First, we will examine legally if TRAI can review the decision or not and further decide the course of action," Sharma said.

Sharma, however, said the decision would be conveyed to telecom operators within two weeks. "Call drop benchmark is 2 per cent, but that does not mean that the operators can have 100 per cent in some areas. They have assured us to improve their performance. We are not here to only criticise them, but help them improve quality of service," Sharma added.

Sharma said TRAI has agreed to add five cities -- Ahmedabad, Indore, Surat, Bhubaneswar and Kolkata -- for the tests and randomly select routes. Tests in the five cities were conducted in September, the report of which is ready.

"We will first share the report with telecom operators tomorrow to study their reservations and then publish it on the website after a week. The report on the 5 cities will give not just statistics, but reasons for call drops," Sharma said.

The regulator will again conduct tests on new routes in seven cities, including Delhi and Mumbai, in December. "We hope that in the next week or so, TRAI will come back to us. We have to give them a chance to respond to our letter. We have not decided on a tariff hike, but operators are going to do something. It will be an individual operator's call, but obviously there will be pressure on tariff if regulation stays," Mathews said after meeting.

World Bank retains India growth forecast at 7.5% for 2015-16

PTI ■ NEW DELHI

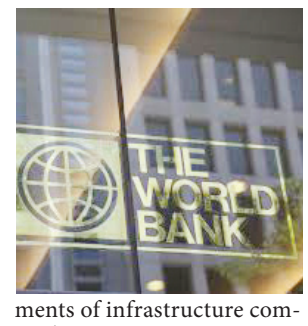

The World Bank on Thursday retained its India's growth forecast for 2015-16 saying it will continue to grow, but the catch is the acceleration year-on-year will be gradual.

"The latest India Development Update expects India's economic growth to be at 7.5 per cent in 2015-16, followed by a further acceleration to 7.8 per cent in 2016-17 and 7.9 per cent in 2017-18," the multilateral lending agency said in a report released.

"However, acceleration in growth is conditional on the growth rate of investment picking up to 8.8% during FY16 to FY18," it added.

Speaking at the launch of the report, World Bank India's Senior Country Economist Frederico Gil Sander said India has taken advantage of the sharp decline in global oil and commodity prices to eliminate petrol and diesel subsidies and increase excise taxes.

"Resources from lower subsidies and higher taxes have been well utilised in lowering deficits and increasing capital expenditure."

The most significant risks to the outlook, he further said, stem from the banking sector and financing requirements of infrastructure companies.

"Public sector banks, which account for three-fourths of domestic credit, are under stress, with a rising share of non-performing assets," Gil Sander noted.

The senior economist felt that India is relatively well-positioned to weather global volatility in the short term.

The report dwelt at length on states, which are now responsible for 57 per cent of spending and account for 16 per cent of GDP. Of this, nearly 74 per cent of the funds are untied compared with an average 57 per cent during the 13th Finance Commission period, getting more flexibility to states.

It suggested that the government need to collect more direct taxes to boost revenues.

"India's direct tax collection is among the lowest in the world. Direct taxes account for a mere 5.7 per cent of GDP in India compared with 11.4 per cent in OECD countries," the report said.

Making a special mention of the Government's efforts for successfully bringing current account deficit (CAD) down to 1.4 per cent in 2015-16, it said CAD is likely to inch up to 1.7 per cent in 2016-17 and 2 per cent in 2017-18.

Stressing on the need to increase export-oriented growth, the report said, "Although India may be able to achieve a fast GDP expansion without export growth for a short period, sustaining high GDP rates over a longer period will require a recovery of exports."

"India has low trade exposure to China while Indian financial markets are fairly closed. India's considerable foreign exchange reserve (nine months of imports) provides an additional buffer," it said.

The Bank is of the view that the 14th Finance Commission recommendation of increasing the share of central divisible pool of tax revenues to 42 per cent from 32 per cent would provide more fiscal space to states.

"... The net impact has been an increase of 0.5 per cent of GDP in overall resource transfer to the states in 2015-16, but there's a much larger increase in untied resources of 1.1 per cent of GDP," the report noted.

SFIO probes 10 companies in Bank of Baroda case

NEW DELHI: The Serious Fraud Investigation Office (SFIO) has started probing 10 companies in connection with the ₹6,100-crore illicit money remittance case involving public lender Bank of Baroda.

Besides SFIO, the case is being investigated by other agencies such as CBI and the Enforcement Directorate.

Sources said SFIO has started investigations into alleged wrong-doings and violations of the Companies Act by some 10 firms relating to the Bank of Baroda matter. These entities are believed to have been used for illicit transactions, they added.

The probe is expected to take about three months to complete and the findings will be shared with other agencies looking into the case, they said.

A multi-disciplinary agency under the Corporate Affairs Ministry, SFIO investigates white-collar crimes, mainly those involving violations of the companies law.

It's alleged that ₹6,172-crore black money was remitted from the bank to Hong Kong camouflaged as payments for non-existent imports of cashew, pulses and rice.

It is also alleged that the amount, which was deposited in 59 accounts of the Ashok Vihar branch in New Delhi in cash as advance for import, was sent to some select companies in Hong Kong.

In the wake of the illicit transaction coming to light, banks are also looking at ways to strengthen the overall surveillance to prevent such instances.

Earlier, this week, Minister of State for Finance Jayant Sinha said the Bank of Baroda scam surfaced in the form of misuse of the circular trading mechanism to take advantage of duty drawbacks. **PTI**

Sebi cuts IPO paperwork; notifies 5-sheet abridged prospectus

NEW DELHI: In a game-changing move, markets regulator Sebi has notified a five-sheet abridged prospectus that companies need to file for public offers -- a step aimed at making it easier for investors to understand key points.

Under the new norms that come into effect from December 1, the abridged prospectus including the application form can't exceed five sheets that would be printed on both sides, a maximum of 10 pages.

Currently, the full prospectus that companies file for their public offers including IPOs runs into 400-500 pages and it has often been felt that the investors find it difficult to get the key information from such bulky documents.

The move would help in reducing the cost for companies.

Sebi said that the "information as is material and appropriate to enable the investors to make an informed decision shall be disclosed in the abridged prospectus".

Also, the companies would need to make these disclosures as per the format specified by Sebi from time to time.

The information which is of generic nature and not specific to the issuer would need to be brought out in the form of a General Information Document (GID) as specified by Sebi.

The Abridged Prospectus would need to be printed in a booklet form of A4 size paper, while the font size can not be "visually smaller than Times New Roman size 11 (or equivalent)" with single-line spacing.

Information required to be given in Tabular Format would not appear in running text format.

"The order in which items appear in the abridged prospectus shall be as specified by Sebi. The application form shall be so positioned that on the tearing-off of the application form, no part of the information given in the abridged prospectus is mutilated," the Securities and Exchange Board of India (Sebi) said in a notification dated October 27. **PTI**

Cipla to sell entire stake in Biomab Holding for $25,775,000

PNS ■ NEW DELHI

Drug major Cipla has entered into an agreement to sell its entire stake in Biomab Holding to Biomab Brilliant Ltd for a consideration of $25,775,000 to focus on biological segment under its arm Cipla BioTec.

"The company has entered into a definitive agreement to sell its entire 25 per cent stake in Biomab Holding Ltd, Hong Kong to Biomab Brilliant Ltd, British Virgin Islands which holds the remaining 75 per cent stake in BHL, for a total consideration of $25,775,000," Cipla said in a statement.

Biomab Holding is focused on developing Biosimilars for the Chinese market, it added.

"Going forward, the company's biological business will be consolidated under Cipla BioTec," the company said.

Cipla BioTec will focus on research, development, manufacturing and marketing of Biosimilars, in the field of cancer, auto-immune diseases, respiratory diseases and diabetes, it added.

SpiceJet COO Sanjiv Kapoor quits

NEW DELHI: SpiceJet's Chief Operating Officer Sanjiv Kapoor on Thursday put in his papers, nearly ten months after original promoter Ajay Singh took over the reins of the budget airline.

Kapoor, 48, was appointed to the post by then owner Kalanithi Maran in November 2013.

"Chief Operating Officer, Sanjiv Kapoor will be leaving the company effective October 31, 2015 after two years with the organisation. He shall be serving his notice period as per the terms of his employment agreement," SpiceJet said in a regulatory filing on Thursday.

His abrupt resignation comes over a year before the expiry of his employment contract, SpiceJet sources said.

"We thank Sanjiv for leading SpiceJet at a very difficult time. He has been, and will remain, a strong and passionate supporter of the airline. We wish Sanjiv all success in his future endeavours," Singh, the airline's chairman and managing director said.

Kapoor is believed to have been sidelined after the new management took over earlier this year following the Marans offloading their entire holding to Singh.

An avid user of micro blogging site Twitter, Kapoor has been a visible face of the no-frills airline and a strong supporter of flash sales of discounted tickets.

"After overcoming significant challenges and under the new ownership, SpiceJet has not only returned to profitability, it has been a fundamental catalyst behind the world leading market growth in India. Thanks to SpiceJet, competition has been kept alive in the Indian airline industry," Kapoor said.

The carrier has seen many senior-level exits since the change in ownership.

The then SpiceJet managing director, S Natrajhen, was the first top official exiting the carrier soon after Singh came onboard. Since then the airline has seen the resignation of seven more senior executives including Kapoor.

The others, who exited from the carrier in the last ten months are then chief commercial officer Kaneswaran Avili, IT head Sudhakar Kondisetty, flight operations head Sandeep Verma and flight safety head V K Khosla.

A co-founder of SpiceJet, Singh, who exited the airline in 2010, took back its control after acquiring the entire 58.46 per cent stake of Kalanithi Maran and Kal Airways Pvt Ltd in February as part of a revival plan. **PTI**

IST LIMITED
CIN : L33301HR1976PLC008316
Regd. Office: Dharuhera Industrial Complex,Delhi Jaipur Highway No. 8, Kapriwas, Dharuhera, Rewari 123106 (Haryana)

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Clause 41 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 14th November, 2015,, inter-alia, to approve & take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th September, 2015.

For IST LIMITED
R.K.Sapra
Company Secretary
FCS: 3785

Date : 29.10.2015
Place : New Delhi

PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LIMITED
(Formerly known as Prakash Woollen Mills Limited)
CIN – L17291UP1979PLC004804
Regd. Office: 18TH Km Stone, Delhi Moradabad Road, NH-24, Village Amhera Distt J P Nagar, Uttar Pradesh-244102

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to clause 41 of the Listing Agreement with the Stock Exchange, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 7th November, 2015 at its Registered office to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results, for the quarter ended 30th September, 2015 among other things.

For PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LIMITED
(Shivangi Agarwal)
Company Secretary

Place: Vill-Amhera(Amroha)
Date: 28.10.2015

METRO RAILWAY, KOLKATA
KOLKATA'S PRIDE

PROVISION OF ONE VEHICLE

Dy. Chief Signal & Telecom Engineer/M, Metro Railway, 33/1, J. L. Nehru Road, Kolkata-700071 for and on behalf of the President of India invites sealed tender from competent and experienced contractors for execution of works as given below : **Name of work:** "Provision of one vehicle (TATA Mobile or Mahindra D-Max or TL DOUBLE CAB or Similar) on hiring basis to perform round the clock duty for transporting staff and materials of S&T department, Metro Railway, Kolkata". **Tender Value :** Rs. 9,53,664/-; **Cost of Tender Document :** Rs. 2,000/-; **EMD :** Rs. 19,080/-; **Date of Selling of Tender Document :** At 11:00 Hrs. of 28.10.2015 to 11:30 Hrs. of 30.11.2015; **Date & Time for Closing & Opening of Tender :** Upto 15:00 Hrs. & 15:30 Hrs. respectively on 30.11.2015; **Tender Notice No. :** MRTS/SG-515/783 Dt. 27.10.15; **Time of completion :** 24 (Twenty four) months from the date of issue of letter of acceptance; Tender documents can be obtained from CSTE's office on production of cash receipt for the cost of Tender Documents (Non-refundable) to be deposited with the Divisional Cashier, Metro Railway, 33/1, J. L. Nehru Road, Kolkata-700071 under head of allocation 93652-99 on any working day between 11:00 Hrs. and 15:00 Hrs. The Tender Documents can also be obtained by Speed Post on payment of Rs. 2,500/- only by sending Demand Draft drawn in favour of "Financial Advisor & Chief Accounts officer, Metro Railway, Kolkata" to the Chief Signal & Telecom Engineer's Office. Tender Documents can also be downloaded from the **Website : www.mtp.indianrailways.gov.in**. More details are available in the website of Metro Railway, Kolkata under the link "Tenders".

Open Tender No. : S&T/Works/16-2014 **Dated : 27.10.2015**

FASTER • SAFER • SMOOTHER • CLEANER

कार्यालय नगर निगम, हरिद्वार

पत्रांक: 2114 / नि0वि0 / 2015–16 — **निविदा सूचना** — दिनांक: 28.10.2015

समस्त पथ प्रकाश उपकरण निर्माता कंपनी / अधिक्रत विक्रेता फर्मों को सूचित किया जाता है कि अर्द्ध कुम्भ मेला–2016 की स्वीकृत निधि के अन्तर्गत स्वीकृत पथ प्रकाश समाग्री की स्थापना / आपूर्ति की जानी है। कार्य की तकनीकी व वित्तीय निविदा दिनांक 18.11.2015 को 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। तकनीकी निविदा उसी दिनांक 18.11.2015 को 3.00 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा उक्त दिनांक 4:00 बजे खोली जायेगी। निविदा के साथ निर्धारित अर्नेस्ट मनी एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0 / राष्ट्रीय बचत पत्र जो कि लेखाधिकारी नगर निगम के नाम पलज होगी संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा समिति / मुख्य नगर अधिकारी को सुरक्षित होगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा की वैधता	कार्य पूर्ण करने का समय
1	22 मी ऊंची हाईमास्ट पर 8 एल0ई0डी0 फ्लड लाईट 280 वाट के साथ हाईमास्ट लाईट की विभिन्न स्थानों पर स्थापना	1.69	3000 + 13.50% वैट	45 दिन	30 दिन
2	11 मी0 ऊंची एस पी 45 स्टील टयूबलर पॉल पर 6 नग एल0ई0डी0 लाईट 100 वॉट फलड लाईट के साथ विभिन्न स्थानों पर स्थापना	0.34	2000 + 13.50% वैट	45 दिन	30 दिन
3	एल0ई0डी0 फ्लड लाईट डाईकास्ट एल्मुनियम बॉडी आईपी 65 मय कलेम्प व नट बोल्ट सहित 1–200 वॉट 2–150 वॉट	0.85	3000+ 13.50% वैट	45 दिन	30 दिन
4	एल ई डी स्ट्रीट लाईट फिटिंग डाईकास्ट एल्मूनियम बॉडी आईपी 65 1–80 वॉट	1.50	3000 + 13.50% वैट	45 दिन	30 दिन
5	**मेन्टीनेंस सामग्री** एल्मूनियम वायर, कॉपर वायर, जी आई पाईप, सोडियम बल्ब, कॉपर चौक, सिंगल फेज टाईमर स्वीच 32 एम्पीयर, सुपर इम्पोस्ड इग्नेटर	0.23	1000 + 13.50% वैट	45 दिन	30 दिन
6	टाटा एस0 बॉडी पर बिजली कार्य हेतु मिनी हाईड्रोलिक लिफ्ट 8.50 मी0	0.24	1000 + 13.50% वैट	45 दिन	30 दिन

1. निविदा प्रपत्र अन्य शर्ते नगर अभियन्ता नगर निगम हरिद्वार के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस देखी जा सकती है। विस्तृत जानकारी नगर निगम, हरिद्वार की वेबसाईट www.nagarnigamharidwar.com व tenders.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। 2. उपरोक्त तिथियों में अवकाश घोषित होने पर आगामी कार्य दिवस की तिथि मानी जायेगी।

मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार

Volkswagen to report impact of emission scandal in India by Nov-end

PNS ■ NEW DELHI

Volkswagen on Thursday said it will come out with details on the impact in India due to the emission scandal that hit the company in many global markets, including the US and Europe, by the end of next month.

The Government had ordered a probe and asked automotive testing agency ARAI to find whether the German carmaker had cheated emission tests in India as it did in the US, where it faces a fine of up to $18 billion.

The Automotive Research Association of India (ARAI) was asked to submit its report by the end of the month.

A meeting was held between Volkswagen Group India representatives and the Ministry of Heavy Industries and ARAI officials on Thursday.

Executives of the group updated the Government officials on the evaluations so far on the ongoing emissions issue with reference to India.

"Since there is a complex combination of several brands, various models, different engine variants and gearboxes as well as different model years that need to be analysed, establishing detailed facts is taking a longer time," Volkswagen Group India said in a statement.

The group will present its results from the evaluations by the end of November 2015.

"During this period, the company representatives will stay in regular touch with ARAI to keep the authorities updated on the analysis. The next steps will depend on the findings from these evaluations," it added.

VW officials rubbished reports that the company would recall about one lakh vehicles in India due to the emission scandal.